



लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
प्रधानमंत्री पुरस्कार

**Prime Minister's Award for
Excellence in Public Administration**

2007 - 2008

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

विषय वस्तु

1. वर्ष 2007-08 के लिए पुरस्कार विजेता
 - (i) बंगलौर महानगरीय परिवहन निगम, कर्नाटक का वित्तीय सम्पोषण
 - (ii) प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रिया आधारित विद्यार्जन (ए बी एल), तमिलनाडु
 - (iii) युद्ध के दौरान बेरुत से भारतीय नागरिकों का निकास
 - (iv) सुरक्षित मातृत्व एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम, गुजरात
 - (v) स्कोर : बिहार में ई-पंजीयन
 - (vi) एम सी ए 21 – एक ई-गवर्नेंस परियोजना
 - (vii) बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यास, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
 - (viii) मणिपुर में कार्मिक सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण
 - (ix) जोखिम प्रबंध प्रणाली (आर एम एस) का कार्यान्वयन
 2. वर्ष 2006-07 के लिए पुरस्कार विजेता
 3. वर्ष 2005-06 के लिए पुरस्कार विजेता
-
-

CONTENTS

1. Awardees for the Year 2007-08
 - (i) Financial Sustainability of Bangalore Metropolitan Transport Corporation, Karnataka
 - (ii) Activity Based Learning (ABL) Methodology for Primary Education, Tamil Nadu
 - (iii) Evacuation of Indian Nationals from Beirut during the war
 - (iv) Safe Motherhood and Child Survival Programme, Gujarat
 - (v) SCORE: e-Registration in Bihar
 - (vi) MCA21 – an e-Governance Project
 - (vii) Improved Health and Sanitation Practices, District Surguja, Chhattisgarh
 - (viii) Computerization of Personnel Information System in Manipur
 - (ix) Implementation of the Risk Management System (RMS)
 2. Awardees for the year 2006-07
 3. Awardees for the year 2005-06
-
-

**पहल : बंगलौर महानगरीय परिवहन निगम,
कर्नाटक का वित्तीय सम्पोषण**

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री उपेन्द्र त्रिपाठी, भा.प्र.से.
तत्कालीन प्रबंध निदेशक
बंगलौर महानगरीय परिवहन निगम लिमिटेड
कर्नाटक सरकार

शहरी समाज के बदलते स्वरूप और ग्रामीण क्षेत्रों से आबादी के पलायन के कारण महानगरीय शहरों का आकार तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। बंगलौर की आबादी 1981 के बाद से दो गुना से भी ज्यादा हो गई है और बंगलौर महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) पर विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की निरंतर बढ़ती मांग का जबर्दस्त दबाव पड़ रहा है।

वर्ष 2001-02 में बीएमटीसी की हालत से बढ़ती आबादी और मांग को पूरा करने के लिए इसके बेड़े में बसों की अत्यंत कमी, पुरानी होती जा रही बसों, यात्रियों में एक बढ़ते असंतोष, यात्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के चलते लागत और समय में वृद्धि, ग्राहकों की शिकायतों को निपटने के लिए कमजोर तंत्र, कर्मचारियों में प्रोत्साहन की कमी आदि का पता चला। सार्वजनिक परिवहन की इस निराशापूर्ण व्यवस्था से शहरी की उत्पादकता को नुकसान पहुंचा।

प्रबंध निदेशक, श्री उपेन्द्र त्रिपाठी ने इस निराशाजनक स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 2003 में कई कदम उठाए। इन प्रस्तावों ने संगठन के पुनरोद्धार के लिए बेड़े में अतिरिक्त बसें शामिल की, प्रशासनिक सुधारों तथा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ-साथ यात्री हितैषी प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया। शीघ्र ही इन प्रयासों के प्रभावी परिणाम सामने आए। बीएमटीसी का मुनाफा 2000-01 के 13 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़कर 2004-05 में 80 करोड़ रुपये, 2005-06 में 115 करोड़ रुपये और 2006-07 में 224 करोड़ रुपये हो गया। इन प्रयासों से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार आया, यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। दुर्घटना दर और वायु प्रदूषण में कमी आई। अपने प्रयासों से श्री त्रिपाठी बीएमटीसी में वित्तीय सम्पोषण लाने में कामयाब हुए और इस मॉडल का अन्य परिवहन निगमों द्वारा अनुकरण किया जा रहा है।

**Initiative - Financial Sustainability of Bangalore
Metropolitan Transport Corporation, Karnataka**

Name of the Awardee - Shri Upendra Tripathy, IAS,
then Managing Director,
Bangalore Metropolitan
Transport Corporation,
Government of Karnataka

With the changing face of urban society and following the influx of population from rural areas, the size of the metropolitan cities is rapidly increasing. Bangalore's population has more than doubled since 1981 and the corresponding demand for reliable public transport has exerted enormous pressure on the Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC).

In the year 2001-02, BMTC had inadequate fleet strength to cater to the growing population and demand, an ageing fleet, a high level of commuter dissatisfaction, rapid decline in ridership, delays in implementation of projects resulting in cost and time over runs, weak mechanisms to address customer grievances and low motivation levels in employees. This sub optimal public transport system was undermining the productivity of the megapolis.

Shri Upendra Tripathy, Managing Director, BMTC undertook a series of interventions and innovations to deal with this dismal situation in the year 2003. These measures included procurement of additional buses, focussing on administrative reforms and commuter-friendly initiatives combined with technological applications, human resources development and capacity building of employees to turn around the organisation. These efforts showed dramatic results within a short time. The profits of the Corporation increased from 13 cr per annum in 2000-01 to Rs 80 cr in 2004-05, Rs. 115 cr in 2005-06 and Rs 224 cr in 2006-07. These initiatives also led to tangible improvements in the quality of public transport services, increase in ridership, lowering of accident rate and improvement in air quality. By his efforts, Shri Tripathy was able to bring financial sustainability to the BMTC, and this model is being copied by other transport corporations.

**पहल : प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रिया आधारित विद्यार्जन (एबीएल) प्रणाली,
तमिलनाडु**

पुरस्कार विजेता का नाम – श्री एम.पी. विजय कुमार, भा.प्र.से.
तत्कालीन आयुक्त, चेन्नई नगर निगम
तमिलनाडु सरकार

विकास से संबंधित अनेक संकेतकों पर ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के बावजूद, तमिलनाडु के सरकारी विद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों और वर्ष-दर-वर्ष पर्याप्त बजटीय आबंटन के बावजूद शैक्षिक उपलब्धियों का गिरता स्तर चौंकाने वाला था।

विद्यार्जन प्रणाली के एक नवप्रवर्तनकारी पद्धति को सही स्थान पर रखने के लिए चेन्नई नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त, श्री विजयकुमार के नेतृत्व में चेन्नई नगर निगम के तेरह विद्यालय साथ हो गए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में खामियों को दूर करने के लिए कार्यकलाप आधारित शिक्षा (एबीएल) पद्धति को विकसित करने और कार्यान्वित करने का कार्य शुरू किया। ऋषि वैली रुरल एजुकेशन सेन्टर की "लर्निंग लैडर्स" जैसी मौजूदा शिक्षण पद्धति से सबक लेकर विजयकुमार और उनकी टीम ने आरंभिक प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों में कार्यकलाप आधारित शिक्षण (एबीएल) की एक अभिनव पद्धति लागू की। इस नई पद्धति में कक्षाओं का माहौल और शिक्षा-ग्राही के पहलुओं को बदलने के साथ-साथ कक्षा I से कक्षा IV तक के छात्रों को लक्ष्य बनाया गया। इसके लिए बच्चे को उसकी शैक्षिक दुनिया का केन्द्र बनाया गया। पाठ्य पुस्तकों को कार्यकलापों के रूप में बांट दिया गया, शिक्षण सामग्री को कलर कोड देकर सोपानों के रूप में व्यवस्थित किया गया, वार्षिक परीक्षा की प्रणाली छमाही कर दी गई है और सम्पूर्ण कक्षा का उपलब्धता संबंधी चार्ट रखा जाता है। कार्यकलाप आधारित शिक्षण पद्धति शिक्षा प्राप्ति के एक मौज-मस्ती, गुणवत्ता अभिमुखी और शिशु केन्द्रित बनाने की दिशा में अभिनव पहल है तथा इसका आसानी से अनुकरण किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप अभी से ही इन छात्रों के शैक्षिक निष्पादन में असाधारण सुधार हैं और इसने उल्लेखनीय रूप से उपस्थिति दर को सुधारा है।

**Initiative - Activity Based Learning (ABL) Methodology for
Primary Education, Tamil Nadu**

Name of the Awardee - Shri M. P. Vijaya Kumar, IAS,
then Commissioner of Chennai
Municipal Corporation
Government of Tamil Nadu

In spite of ranking high on most of the development indicators, the Government schools of Tamil Nadu have an alarmingly low level of academic achievement in spite of the Government's best efforts to ensure universal primary education and substantial budgetary allocation year after year.

Under the leadership of Shri Vijaya Kumar, the then Commissioner of Chennai Municipal Corporation, thirteen Chennai Corporation schools got together to put in place an innovative method of learning methodology. They began working on developing and implementing the Activity Based Learning (ABL) methodology to address gaps in primary education. Drawn from the already existing teaching methodologies like 'Learning Ladders' of Rishi Valley Rural Education Centre, Shri Vijaya Kumar and his team applied Activity Based Learning (ABL) to schools at primary education level, initially as a pilot project. The new methodology targeted students of standard I to IV by transforming the classroom environment and learning dynamics, by making the child the centre of his/her academic world. Text books were broken down into activities, learning materials were colour coded and arranged in ladders, annual exam was eliminated and achievement chart maintained for the whole class. ABL methodology is a ground-breaking effort in making learning fun, quality oriented and child centred, and can be replicated easily. It has resulted in a remarkable improvement in the academic performance of these students and also improved the attendance. The method is now used in primary schools all over the State and has also been adopted by other States.

पहल : युद्ध के दौरान बेरुत से भारतीय नागरिकों का निकास

पुरस्कार विजेता का नाम – श्रीमती नेंगचा ल्होबुम, भा.वि.से.
लेबनान में भारत की राजदूत

इजरायल ने 12 जुलाई, 2006 को लेबनान पर एक हवाई हमला कर दिया। इसकी वजह से अवसंरचना को शामिल करते हुए नागरिक क्षेत्रों, सड़कों, पुलों, नगरों, गांवों आदि को भारी नुकसान पहुंचा। इजरायल ने पूरी तरह से एक सामुद्रिक और हवाई घेराबन्दी भी कर दी थी। अगले 33 दिनों में 1200 से ज्यादा नागरिक (एक भारतीय सहित) मारे गए, 4000 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए, 10 लाख से ज्यादा लोक विस्थापित हो गए और लेबनान का बुनियादी ढाँचा तहस-नहस हो गया। नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी से आतंक का माहौल पैदा हो गया और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का एक सबसे बड़ा अभियान चलाना पड़ा। लेबनान स्थित भारतीय दूतावास का कार्य लेबनान में रह रहे भारतीय समुदाय के लगभग 12,000 लोगों का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

श्रीमती नेंगचा ल्होबुम, भारतीय राजदूत ने तुरंत कदम उठाते हुए लेबनान में भारतीय समुदाय के लोगों और संस्थाओं से संपर्क बनाया ताकि लेबनान से बाहर जाने के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों की पहचान की जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके। एक प्रमुख समस्या यह थी कि अनेक भारतीयों ने देश में कानूनी रूप से प्रवेश नहीं किया था। उनके पासपोर्ट और प्रवासन स्थिति में अनियमितताओं को दूर करने की एक बड़ी समस्या थी। भारतीय राजदूत और दूतावास के समक्ष जमीनी, समुद्री और हवाई मार्गों के जरिए निष्कासन के लिए रूपरेखा तैयार करने और साखों-सामान की व्यवस्था करने, विदेशक मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, भारतीय नौसेना, एयर इंडिया सीरिया, साइप्रस, इजरायल में भारतीय दूतावासों तथा लेबनान अधिकारियों से संपर्क करने जैसी चुनौतियां थीं।

इन कठिनाई के बावजूद इस राजदूत और छोटे से दूतावास ने समुद्र से एक बड़े पैमाने पर निकासी का आयोजन किया। यह निष्कासन अभियान 39 दिन चला जिसमें 1863 भारतीयों और 524 दक्षिण एशियाई लोगों को बिना किसी शुल्क के सुरक्षित अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना ने बेरुत के छह फेरे लगाए।

Initiative - Evacuation of Indian Nationals from Beirut during the war

Name of the Awardee - Mrs. Nengcha Lhouvum, IFS,
Ambassador of India in Lebanon

On July 12, 2006, Israel launched an air attack on Lebanon. This resulted in destruction of civilian areas including infrastructure like roads, bridges, towns, villages, etc. Israel also imposed a full naval as well as air blockade. In the next 33 days, over 1200 civilians (including one Indian) were killed, over 4000 wounded, a million displaced and Lebanon's infrastructure destroyed. The bombing of civilian areas created panic, triggering one of the biggest evacuation operation of Indian Nationals abroad. The Indian Embassy at Lebanon was tasked to ensure the safety and security of the Indian community which was estimated about 12,000.

Mrs. Nengcha Lhouvum, the Indian Ambassador acted quickly by establishing contact with Indian community and Indian associations in Lebanon so that the persons of Indian origin, desiring to be evacuated could be identified and brought to safety. There was a major problem as many Indian had not legally entered the country. A big difficulty was resolving irregularities in passports and immigration status. The challenges before the Ambassador and the Indian Embassy was to work out the modalities and logistics of evacuation through land, sea and air; liaising with MEA, Ministry of Overseas Indians Affairs, Indian Navy, Air India, Indian Embassy in Syria, Cyprus, Israel and Lebanese authorities.

Despite these difficulties, the Ambassador and the small embassy organised a large scale evacuation by sea. The evacuation operation lasted for 39 days in which the Indian Navy made six forays to Beirut to evacuate 1,863 Indians and 524 South-Asians free of charge. Mrs. Nengcha Lhouvum, however, personally organised and supervised this evacuation with extreme dedication and efficiency.

पहल : सुरक्षित मातृत्व एवं बाल संरक्षण कार्यक्रम

पुरस्कार विजेता का नाम – डॉ. अमरजीत सिंह, भा.प्र.से.
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
गुजरात सरकार

भारत में मातृत्व मृत्यु एक गंभीर समस्या है – मृत्यु दर लगभग 350 से 400 प्रति 100 हजार बाल जन्म है। गुजरात में, प्रतिवर्ष प्रसव के दौरान प्रति 100 हजार जीवित जन्मों पर 469 माताओं की मृत्यु हो जाती है। मातृत्व मृत्यु का प्रमुख कारण यह था कि अनेक प्रसव अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में किए जा रहे थे।

उच्च मातृत्व मृत्यु दर (एम एम आर) और शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) की परेशानियों से सबक लेकर डॉ. अमरजीत सिंह, तत्कालीन आयुक्त, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ, गुजरात सरकार ने अप्रैल, 2005 में "चिरंजीवी योजना" नामक एक योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य उन माताओं जो गरीबी रेखा से नीचे थी और जो आमतौर पर स्वास्थ्य कवरेज के बारे में अल्पज्ञ रहीं हैं को संस्थागत प्रसव के लिए पहुंच को बेहतर बनाना था।

इस संदर्भ में सरकार ने सुरक्षित प्रसव उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा निजी व्यावसायिकों को सूचीबद्ध करके राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करने के विचार की शुरुआत की। ये व्यावसायिक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दक्ष प्रसूति-विज्ञान देखभाल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। इसके बदले में सरकार ने उन्हें प्रति एक सौ प्रसवों पर एक समान फीस अदा की जिसका एक भाग अग्रिम रूप से अदा किया गया।

इस प्रकार, चिरंजीवी योजना ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को या तो सरकारी अथवा निजी स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति प्रदान की। इसमें आने-जाने का भाड़ा तथा आने वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रोत्साहनों जैसी अप्रत्यक्ष लागतें भी शामिल हैं। इस योजना ने मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल की कवरेज को बेहतर बनाया है और डॉ. अमरजीत सिंह इस विचार को प्राप्त एवं कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं।

Initiative - Safe Motherhood and Child Survival Programme

Name of the Awardee - Dr. Amarjit Singh, IAS
Secretary, Health & Family
Welfare Department,
Government of Gujarat

Maternal mortality is a serious problem in India, the mortality rate being about 350 to 400 per 100 thousand child births. In Gujarat in the year 2003, 469 mothers died during delivery per 100 thousand live births. The primary reason for maternal deaths was that many deliveries were being conducted by untrained persons in unhygienic conditions.

Guided by the concerns over high Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR), Dr. Amarjit Singh, the then Commissioner, Health and Medical Services, Government of Gujarat initiated the scheme called "Chiranjeevi Yojana" in April 2005. The aim was to improve access to institutional delivery for those mothers who were below the poverty line and who remained generally under-represented in terms of health coverage.

In this context, the Government initiated the idea of utilizing the existing resources of the state by empanelling existing private practitioners for providing safe delivery. These practitioners were made responsible for providing skilled obstetric care to families below the poverty line. In return, the Government paid them a flat fee per hundred deliveries, a part of which was paid in advance.

Chiranjeevi Yojana, thus, allows families living below the poverty line to use either public or private health facilities, free of cost. It also covers indirect costs such as transportation and incentives for any accompanying person. The scheme has, improved coverage of maternal health care, and Dr. Amarjit Singh has been responsible for conceiving and implementing this idea.

पहल : स्कोर : बिहार में ई-पंजीकरण

- दल के सदस्यों का नाम –
1. श्री अनिल कुमार, भा.प्र.से.,
आई.जी., पंजीकरण
 2. श्री दिलीप कुमार, ए.आई.जी., पंजीकरण
 3. श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह
 4. श्री बरुना नंदन सिंह
 5. श्री निर्मल किशोर प्रसाद, एस.एस.ए.
 6. श्री संजय कुमार, एस.एस.ए.
बिहार सरकार

बोझिल प्रक्रिया, विलम्ब और भ्रष्टाचार बिहार में सम्पत्ति पंजीकरण की परम्परागत व्यवस्था की विशेषता है। पंजीकरण बहुत उबाऊ एवं समय नष्ट करने वाला था। रजिस्टर में दस्तावेजों की नकल हाथ द्वारा किए जाने का तरीका विफल हो चुका है। रिकार्ड अनुरक्षण का बकाया काम लगभग 7 से 8 वर्षों का है।

बिहार सरकार का पंजीकरण विभाग पंजीकरण प्रक्रिया में कार्य कुशलता और पारदर्शिता तथा पणधारियों के आत्मविश्वास को वापस लाना चाहता है। उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में सम्पत्तियों के ई-पंजीकरण हेतु बी स्कोर (कम्प्यूटरीकृत पंजीयन का बिहार तरीका) नामक एक नवप्रवर्तनकारी आई सी टी आधारित सम्पूर्ण समाधान अभिकल्पिक एवं कार्यान्वित किया गया है। इसमें राज्य के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में कम कागजी तथा निपुणता-की-स्थिति अभिलेखागार व्यवस्था के साथ सम्पूर्ण प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

राज्य के सभी 105 रजिस्ट्री कार्यालय भाड़ा आधारित मॉडल पर लागत प्रभावी हार्डवेयर तीन माह के एक रिकार्ड समय में स्कोर समर्थ कर लिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व में सुनम्य बढ़ोतरी बी स्कोर संस्था में निधि की संभूति, नष्ट रोजगार के अवसरों का सृजन एवं उद्यमियों के बीच स्वरूप प्रतियोगिता हुई है। बी स्कोर निपुणता की स्थिति प्रौद्योगिकियों यथा अंगुलि छाप जीवसांख्यिकी साधनों का मुद्रण, वेब कैमरा, स्कैनरों इत्यादि का नवप्रवर्तनकारी उपयोग निरूपण भी करता है। ये पूरी योजना स्वपोषित एवं प्रमाणनीय है; इसने गत एक वर्ष की अवधि में प्राचीन युग के सरकार के कार्य वातावरण को पूर्णतः बदल दिया है और राज्य में सम्पत्ति पंजीकरण की 200 वर्षों पुरानी हस्तचालित व्यवस्था को प्रभावी रूप से बदल दिया है।

Initiative - SCORE: e-Registration in Bihar

Names of the
Team Members -

1. Shri Anil Kumar, IAS, IG Registration
2. Shri Dilip Kumar, AIG Registration
3. Shri Birendra Kumar Singh
4. Shri Baruna Nandan Singh
5. Shri Nirmal Kishor Prasad, SSA
6. Shri Sanjay Kumar, SSA

Government of Bihar

The conventional system of property registration in Bihar was characterized by cumbersome procedures, delays and corruption. Registration was very tedious and time consuming. The system of manually copying deeds in registers had collapsed. The backlog of record maintenance was about 7 to 8 years.

The Registration Department of the Bihar government wanted to bring in efficiency and transparency in the registration process and bring back the confidence of the stakeholders. To meet their expectations, an innovative ICT based complete solution for e-registration of properties in the State named Bi SCORE (Bihar System of Computerized Registration) was designed and implemented. It involves complete automation of processes with less paper and state-of-art record archival system at all registry offices of the State.

All 105 registry offices of the state have been SCORE-enabled in a record time of three months with a cost effective Hardware on Hire Basis (HOHB) model. This has resulted in increase in state revenue, accrual of funds in BiSCORE society and created new job opportunities, and a healthy competition amongst the entrepreneurs. BiSCORE also demonstrates the innovative use of state-of-art technologies like finger print biometric devices, web camera, scanners, etc. The entire scheme is self-sustainable and verifiable. It has been completely adapted during the last year to the age-old government working environment and has effectively changed the 200 year old system of manual property registration in the State.

पहल : एमसीए 21 – एक ई-गवर्नेंस परियोजना

- टीम के सदस्यों का नाम –
1. श्री अनुराग गोयल, भा.प्र.से., सचिव, एम.सी.ए.
 2. श्री युधवीर सिंह मलिक, भा.प्र.से.,
तत्कालीन संयुक्त सचिव, एम.सी.ए.
 3. डॉ. (सुश्री) शीला भिडे, भा.प्र.से.,
तत्कालीन संयुक्त सचिव, एम.सी.ए.
 4. श्री आर. चन्द्रशेखर, भा.प्र.से.,
तत्कालीन अपर सचिव, (आई.टी.)
 5. श्री जितेश खोसला, भा.प्र.से.,
संयुक्त सचिव, एम.सी.ए.
 6. श्री एस. श्रीधरन, कनिष्ठ विश्लेषक, एम.सी.ए.
कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत किसी भी कम्पनी को कम्पनी पंजीयक (आरओसी) के कार्यालय में हर वर्ष जानकारी फाइल करनी होती है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट संबंधी कुछ कार्यों, जैसे – पंजीकृत आदि के लिए (आर ओ सी) से अनुमति लेनी होती है। पिछले वर्षों के दौरान इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों की संख्या 1956 में लगभग 30,000 से बढ़कर 2007 में 8 लाख से अधिक पहुंच गई है। इससे कम्पनी पंजीयक के कार्यालय पर काम का दबाव काफी बढ़ गया और रिटर्न फाइल करने और अनुमोदन प्राप्त करे की सांविधिक प्रक्रिया अत्यंत मुश्किल हो गई, जिसकी वजह से अनावश्यक देरी होने लगी और रिटर्न फाइल करने और/अथवा आरओसी से अनुमोदन प्राप्त करने के कार्यों में कारपोरेट क्षेत्र भी कई श्रम-दिवस का नुकसान होने लगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय प्रबंधन तथा प्रवर्तन के अनुपालन से संबंधित अपने विनियामक कार्य नहीं कर पा रहा था।

इस समस्या से निपटने के लिए, सरकारी ने 'एमसीए 21' की अवधारणा तैयार की जिसमें कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के लिए, कहीं से भी, किसी भी समय, विशेष रूप से बिना किसी कागजी कार्रवाई के सहज संपर्क सुनिश्चित किया गया। परियोजना में प्रक्रिया को री-इंजीनियरिंग, पुराने दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, ई-फायलिंग और एक आसान विधायी ढांचा तैयार करने के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन का कार्य शामिल था। इससे कारपोरेट क्षेत्र के लिए बिना श्रम दिवसों का नुकसान उठाए अपनी रिटर्न फाइल करना और समयबद्ध तथा पारदर्शी तरीके से

Initiative - MCA21- an e-Governance Project

Names of the

- Team Members -
1. Shri Anurag Goel, IAS, Secretary, MCA
 2. Shri Yudhvir Singh Malik, IAS, then JS, MCA
 3. Dr. (Ms.) Sheela Bhide, IAS, then JS, MCA
 4. Shri R. Chandrashekhar, IAS, then AS(IT)
 5. Shri Jitesh Khosla, IAS, JS, MCA
 6. Shri S. Sridharan, JA, MCA
Ministry of Corporate Affairs,
Government of India

Any company registered under the Companies Act 1956 requires filing information on an annual basis with the Registrar of Companies (RoC). In addition, certain corporate actions such as change of registered office, change of name, etc., requires approval from the RoC. Over the years, the number of companies registered under this Act have increased from about 30,000 in 1956 to more than 8 lakhs in 2007. This has created a tremendous pressure on the office of the RoCs and the process of statutory filings and seeking approvals became extremely inefficient, leading to inordinate delays and the corporate sector losing numerous man-days in filing of returns and/or seeking approvals from the RoC. The MCA could not perform its regulatory functions relating to compliance management and enforcement.

To tackle this problem, Government of India conceptualised 'MCA21' which ensured an anywhere, anytime, secure access for *Ministry of Corporate Affairs (MCA)* services, practically, free of paper. The project involved re-engineering of processes, digitisation of legacy of documents, enabling of e-filing and amendments in the Companies Act and rules to create an enabling legal framework. It has enabled corporate sector to file their returns and obtain approvals from the RoC in a time-bound and transparent manner, without loss of man-days. This approach has allowed the Government to maintain focus on statutory and value-based aspects of the work

आरओसी से अनुमोदन प्राप्त करना आसान हो गया। इस कदम से सरकार के लिए कार्य को सांविधिक तथा मूल्य आधारित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना सहज बना जबकि अधिकांश कार्य प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से निपटाए जाने लगे हैं। इससे एमसीए को सुविधाप्रदाता के रूप में फिर से अपने कदम जमाने में मदद मिली है और कारपोरेट क्षेत्र तथा हितधारकों को देश के लक्षित आर्थिक विकास की उपलब्धियों में अपना योगदान देना आसान हो गया है।

Category Team

while other tasks are largely handled through the use of technology. MCA has been able to reposition itself as a facilitator enabling the corporate sector and other stakeholders to contribute to the achievement of the targeted economic growth of the country.

पहल : बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभ्यास, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

- दल के सदस्यों का नाम – 1. डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से., जिला अधिकारी
2. सुश्री रितु सेन, भा.प्र.से., जिला अधिकारी
(डी एवं आर)
जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़ सरकार

सरगुजा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लेकिन सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। यहां साक्षरता की दर कम और कुपोषण तथा शिशु मृत्युदर अत्यधिक है। कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक आदिम जनजातीय समुदाय के लोग हैं। जल निकायों और पेयजल सुविधाओं के खराब प्रबंधन, आम लोगों में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति जागरुकता की कमी की वजह से जिले में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अच्छी नहीं है। स्वच्छता का खराब प्रबंधन भी शिशु मृत्युदर अधिक होने का एक बड़ा कारण है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) पर कार्य करने का निर्णय लिया।

इन अधिकारियों ने “अभिसरण का मॉडल” कार्यान्वित करने की पद्धति अपनाई जिसमें अनेक समरूप विभागों ने पंचायतों के साथ मिलकर काम किया। मौजूदा संसाधनों का प्रयोग करके वे सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहे और इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत और ग्रामीण विभाग जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बिन्दु तैयार किए। इसके पहचान किए गए 245 जिलों के 85,000 घरों के शौचालय और 256 विद्यालयों में 2703 स्वच्छता परिसरों का निर्माण संभव हुआ। निर्माण कार्य की निगरानी, जुमाने लगाने और परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के माध्यम से समुदायों ने इनका स्वामित्व संभाल लिया। हैण्डपम्पों तक समुचित पहुंच उपलब्ध करा कर, पेयजल की समस्या भी काफी हद तक हल कर ली गई है। व्यक्तिगत साफ-सफाई के प्रति सजगता बढ़ी है और गांवों में स्नानघरों के इस्तेमाल में यह नजर आ रही है। पंचायतों द्वारा निगरानी के चलते विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति बढ़ी है। समरूप विभाग अब बेहतर परिणामों के लिए तालमेल के साथ कार्य कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में साफ-सफाई के प्रति जागरुकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों के प्रयास के फलस्वरूप जिले में लोगों की स्थिति में सुधार हुआ है।

Initiative - Improved Health and Sanitation Practices, District Surguja, Chhattisgarh

Names of the

- Team Members -
1. Dr Rohit Yadav, IAS, District Collector
 2. Ms. Ritu Sain, IAS, DC (D&R)
- District : Surguja
Government of Chhattisgarh

Surguja is the largest but one of the most backward districts of Chhattisgarh with low rates of literacy and a high incidence of malnutrition and infant mortality. Primitive tribal communities constitute over 50 percent of population. Poor systems of management of water bodies and drinking water facilities, lack of public health and hygiene awareness contributed to the poor health conditions prevailing in the district. The prevailing High Infant Mortality Rate is also largely attributed to poor sanitation. It was in this context that the District Administration, decided to work on Total Sanitation Campaign (TSC).

The officers adopted innovative methods of implementing a 'model of convergence' where a number of line departments worked together with *Panchayats*. Using existing resources, they could produce positive changes and worked out points of linkages among various sectors like health, education, *panchayats* and rural development. This facilitated, within a short period, construction of more than 85,000 individual household toilets and 2,703 sanitation complexes in schools of 256 identified *Panchayats*. Communities took ownership of the project through monitoring of construction, imposition of fines and management of assets. By providing proper access to handpumps, the problem of drinking water was, to a great extent, also solved. Awareness about personal hygiene increased, and this is visible in the increased use of bathrooms in villages. *Panchayat* vigil has brought an improvement in teachers' attendance. Line departments now act in synergy with better results. There has been a marked improvement in the hygiene awareness of the school-going children. The efforts of the officers has resulted in better condition for the people of the district.

पहल : मणिपुर में कार्मिक सूचना प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

- दल के सदस्यों का नाम –
1. श्री जरनैल सिंह, भा.प्र.से.,
तत्कालीन प्रधान सचिव
 2. श्री आर.आर. रश्मि, भा.प्र.से.
 3. श्री एस. सुन्दरलाल सिंह, भा.प्र.से.
 4. श्री के. राधाकुमार सिंह, भा.प्र.से.
 5. श्रीमती एम. बुद्धिमाला देवी
 6. श्रीमती ओ. शालिजा चानु
मणिपुर सरकार

1970 और 1980 दशकों के दौरान, मणिपुर सरकार ने प्रभावी लोक सेवा प्रदायगी के लिए संस्थानिक तंत्र की सुदृढता पर अधिक जोर डाले बिना एक महत्वकांक्षी रोजगार प्रसार योजना का आरंभ किया था। तथापि, तीव्र सरकार ने झूठी तथा तदर्थ नियुक्तियों जैसे अनाचार के लिए अवसर का भी सृजन किया। पदों को अक्सर मंत्रिमंडल जैसे समर्थ प्राधिकारी की उपयुक्त मंजूरी के बिना भरा जाता था या अधिकारियों का पहाड़ों से समतल भूभाग में स्थानान्तरण एवजी की तैनाती के बिना होना इत्यादि के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में उपलब्धताओं तथा सेवा की गुणवत्ता का गंभीर अभाव हुआ है। पदों के सृजन के रिकार्ड गायब अथवा नष्ट पाए गए थे।

इसके अतिरिक्त, अनुमादित 70,000 कर्मियों के कुल कार्यबल हेतु चौथे एवं पांचवें वित्त आयोग अवार्ड के कार्यान्वयन ने राज्य द्वारा सामना किये जा रहे वित्तीय संसाधन की चरमराहत को बढ़ा दिया।

सरकार के अंदर रोजगार की प्रक्रिया एवं कार्यविधि के संशोधन और वेतन पर व्यय को संचालित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने एक कार्मिक सूचना प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण (सी पी आई एस) की अभिकल्पना हेतु एक पहल का आरंभ किया। इसकी सिफारिश वित्तीय संसाधन तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 जो अनुबद्ध समय सीमा के अंदर वित्तीय अभाव को नियंत्रित करने के लिए अनुशासनिक उपाय का समर्थन करती है द्वारा की गई। “मणिपुर लोक सेवकों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अधिनियम, 2006” के कार्यपालकों को शामिल करते हुए सभी लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से राज्य द्वारा उनके अनाधिकृत अनाचरण/आचरण द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी हैं, ने आगे सी पी आई एस की आवश्यकता पर बल दिया है।

Initiative - Computerization of Personnel Information System in Manipur

Names of the

- Team Members -
1. Shri Jarnail Singh, IAS, then Chief Secretary
 2. Shri R.R.Rashmi, IAS
 3. Shri S.Sunderlal Singh, IAS,
 4. Shri K. Radhakumar Singh, IAS,
 5. Smt. M. Budhimala Devi
 6. Smt. O.Shaliza Chanu
Government of Manipur

During the 1970s and 1980s, Government of Manipur embarked upon an ambitious employment expansion plan without much focus on strengthening the institutional mechanism for effective public service delivery. However, the rapid expansion also created opportunities for malpractices like fake and adhoc appointments. Posts were often filled without appropriate sanctions from a competent authority, officers were transferred from hills to the plains without posting of substitutes, etc, resulting in serious deficiencies in availability and quality of services in the hill regions. Records of post creations were found missing or destroyed.

In addition, the implementation of the fourth and the fifth Pay Commission Award, for a total workforce of an assumed number of 70,000 employees, added to the financial resource crunch, faced by the State.

For rectifying the process and procedures for employment within the Government and controlling expenditure on salaries, officers of the State Government started an initiative to design a Computerised Personnel Information System (CPIS). It was recommended by the Fiscal Resource and Budget Management Act, 2005 which advocated disciplinary measures to control the financial deficit within the stipulated timeframe. Enactment of "Manipur Public Servants Personal Liability Act 2006", under which, all public servants, including the political executive, are personally liable to make good the loss incurred by the State on account of their unauthorized omissions/commissions, further strengthened the need for CPIS.

The implementation of CPIS has provided many benefits, it has

सी पी आई एस के कार्यान्वयन ने बहुत से लाभ प्रदान किए हैं, इसने राज्य डाटा केन्द्र में मंजूर किए गए पद के संबंध में प्रत्येक विभाग को कर्मचारी की संक्षिप्त जीवनी के एक सही डाटाबेस को जारी रखने में सहायता प्रदान की है। अब हर विभाग सीधे अपने कार्यालय से राज्य डाटा केन्द्र को डाटाबेस अद्यतन करने में सक्षम है, जो बदले में वित्त विभाग को विभाग से रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को सृजित करने में सहायता प्रदान करती है। इसने अन्ततोगत्वा राज्य के व्यय को नियंत्रित करने में राजकोष की मदद की है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में अब सभी कर्मचारी उनकी तैनाती के स्थान पर हैं।

Category Team

enabled every department to maintain a correct database of employee profiles vis-à-vis sanctioned post in the State Data Centre. Every department is now able to update the database to the State Data Centre directly from their office, which in turn helps finance department to generate any kind of report without waiting for the reports from the department. This ultimately has helped the Treasury to control State's expenditure. Backward regions in the State now have all their officials in the place of posting.

पहल : जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का कार्यान्वयन

संगठन का नाम – प्रणाली तथा आँकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड
भारत सरकार

देश में आर्थिक विकास के साथ-साथ व्यापार भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन बुनियादी ढांचा इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर नहीं चल पाया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और सुरक्षा के बदलते परिदृश्य के प्रत्युत्तर में दिसम्बर, 2005 में जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की शुरुआत की गई थी। इससे सामंजस्यता, पारदर्शिता और दक्षता में काफी वृद्धि हुई जिससे व्यापारियों तथा अन्य हितधारकों में विश्वास पैदा करने में सहायता मिली।

आरएमएस ने भारतीय बंदरगाहों पर आयातित सामान को हैण्डल करने के तौर-तरीकों में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। आरएमएस न केवल व्यापार सहज बनाने, राजस्व बढ़ाने, भ्रष्टाचार घटाने की दिशा में कार्य करता है बल्कि यह हमारे देश के बंदरगाहों पर सीमा सुरक्षा को भी मजबूत करता है। इसमें खुफिया सूचना हासिल करने की अन्तःनिर्मित क्षमता है, जोखिम प्रबंधन प्रभाग (आरएमडी) इस पर निरंतर नजर रखता है और इसे अपडेट करता रहता है। इसके फलस्वरूप, आयातित सामान के प्रत्येक कार्गो का मूल्यांकन और जांच का कार्य मानवीय सहायता से करने की बजाय अब आरएमएस कुल आयात का 50 प्रतिशत तक केवल कुछ मिनटों में ही निपटा सकता है। सभी 23 बंदरगाहों पर जहां आरएमएस का बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन काम कर रहा है, ख्याति प्राप्त तथा नियमों का पालन करने वाले आयातकों को उनके कार्गो को तत्काल निकासी देकर लाभान्वित कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि अनुपालन न करने वालों की जांच की जाए। इस प्रकार, आरएमएस की उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि यह नियमों, कानूनों का पालन करने वाले आयातकों में आचरण संबंधी बदलाव लाकर उनमें अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।

Initiative - Implementation of the Risk Management System (RMS)

Name of the Organisation - Directorate General of Systems & Data Management,
Central Board of Excise and Customs
Government of India

With the economic growth of the country, trade has multiplied whereas infrastructure has not kept pace. In response to the changing trade and security landscape nationally and internationally the Risk Management System (**RMS**) was introduced in December, 2005. It brought in a great degree of consistency, transparency and efficiency, which helped building of confidence among traders and other stakeholders.

The RMS has demonstrated the potential to bring about transformational change in the way imports are handled at India's ports. RMS not only works towards facilitating trade, increasing revenues, reducing corruption, it also strengthens the border security at the ports. It has in built an 'intelligence' that is constantly monitored and updated by the Risk Management Division (RMD). As a result, instead of manually evaluating and examining every import cargo now the RMS can clear up to 50% of all imports in a matter of a few minutes. The RMS's intelligent design rewards the reputed and compliant importers, at all the 23 ports where RMS is in operation, by almost instantly facilitating their cargo and ensures that those who are non-compliant are subject to examination. Thus, a significant outcome of RMS is that it is promoting a culture of compliance by bringing about behavioural change among the non-compliant importers.

**दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को प्रदान किये गये
वर्ष 2006-07 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
प्रधानमंत्री पुरस्कार**

1.	पहल – पुरस्कार विजेता का नाम :	त्रिची सामुदायिक पुलिस व्यवस्था श्री जे.के. त्रिपाठी, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध स्कन्ध तमिलनाडु सरकार
2.	पहल – पुरस्कार विजेता का नाम :	मातृत्व एवं बाल संरक्षण तथा स्वास्थ्य में सुधार करना (तमिलनाडु) सुश्री शीला रानी चुकंट, भा.पु.से. अध्यक्ष तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड
3.	पहल – पुरस्कार विजेता का नाम :	ठाणे एवं नागपुर (महाराष्ट्र) शहरों का बदला स्वरूप डॉ. टी. चन्द्रशेखर, भा.प्र.से. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई
4.	पहल – दल के सदस्यों के नाम:	लोकवाणी-नागरिकों को अडि कारिता देने का एक प्रयास (उत्तर प्रदेश) (i) श्री आमोद कुमार, भा.प्र.से. (ii) सुश्री जोहरा चटर्जी, भा.प्र.से. (iii) श्री एस.बी. सिंह

**Prime Minister's Awards for Excellence in
Public Administration for the year 2006-07
presented on 21st April, 2008**

1.	Initiative - Name of the Awardee :	Trichy Community Policing Shri J.K. Tripathy, IPS Inspector General of Police, Economic Offences Wing Government of Tamil Nadu
2.	Initiative - Name of the Awardee :	Improving Maternal and Child Survival and Health (Tamil Nadu) Ms. Sheela Rani Chunkath, IAS Chairperson, Tamil Nadu Industrial Investment Corpn. Ltd.,
3.	Initiative - Name of the Awardee :	Changing Face of Thane & Nagpur Cities (Maharashtra) Dr. T. Chandra Shekar, IAS Vice President & CEO, Maharashtra Housing & Area Development Authority, Mumbai
4.	Initiative - Names of the Team Members :	Lokvani-an effort to empower the Citizen (Uttar Pradesh) (i) Shri Amod Kumar, IAS (ii) Ms. Zohra Chaterjee, IAS (iii) Shri SB Singh (iv) Shri Uma Shankar Singh

		(iv) श्री उमा शंकर सिंह (v) श्री देवेन्द्र पाण्डे (vi) श्री ए.पी. सिंह
5.	पहल – दल के सदस्यों के नाम :	सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा पहल (i) श्री गौतम गुहा, भा.ले. तथा ले.प. स व ा (ii) श्री एल.एस. सिंह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (iii) श्री राजेश गोयल, भा.ले. तथा ले.प. सेवा (iv) श्री नीलेश कुमार शाह, भा.ले. तथा ले.प. सेवा
6.	पहल – दल के सदस्यों के नाम :	(v) डॉ. आशुतोष शर्मा, भा.ले. तथा ले.प. सेवा संरक्षित क्षेत्रों का कारगर प्रबंधन—उत्तराखंड
7.	पहल – दल के सदस्यों के नाम :	(i) सुश्री ज्योत्सना स्टिलिंग, भा.वन.से. (ii) श्री ए.के. बनर्जी, भा.वन.से. अनारक्षित टिकट प्रणाली—रेल मंत्रालय 1. श्री विक्रम चोपड़ा, आई आर टी एस 2. डॉ. राजेश नारंग 3. श्री टी वेंकटसुब्रमणियन्, आईआरएसएमई 4. श्री आर चन्द्रशेखर 5. श्री रमन बंसल 6. सुश्री मोनिका मल्होत्रा

5.	Initiative -	(v) Shri Devendra Pande (vi) Shri A P Singh
		Information Technology Audit Initiative
6.	Names of the Team Members :	(i) Shri Gautam Guha, IA&AS (ii) Shri L S Singh, IA&AS (iii) Shri Rajesh Goel, IA&AS (iv) Shri Neelesh Kumar Sah, IA&AS (v) Dr. Ashutosh Sharma, IA&AS
		Effective Management of Protected Areas -Uttarakhand
7.	Names of the Team Members :	(i) Ms. Jyotsna Sitling, IFS (ii) Shri A.K.Banerjee, IFS
		Unreserved Ticketing System - Ministry of Railways
	Names of the Team Members :	1. Shri Vikram Chopra, IRTS 2. Dr. Rajesh Narang 3. Shri T. Venkatasubramanian, IRSME 4. Shri R.Chandrashekar 5. Shri Raman Bansal 6. Ms. Monica Malhotra 7. Shri Alok Chaturvedi, IRTS 8. Shri T. Kiran Kumar 9. Shri Kaustav Mandal 10. Shri Debashish Ghosh

		<p>7. श्री आलोक चतुर्वेदी, आई आर टी एस</p> <p>8. श्री टी किरण कुमार</p> <p>9. श्री कौस्तव मंडल</p> <p>10. श्री देवाशीष घोष</p> <p>11. श्री जी.जे. जैरी औरिक सिंह</p> <p>12. श्री कपिल भगत</p> <p>13. श्री प्रोजिनेश विस्वास</p> <p>14. श्री दिलीप मिश्रा</p> <p>15. श्री संदीप कुमार वत्स</p> <p>16. श्री आशीष अरोड़ा</p> <p>17. श्री गौरव डी. जौहरी</p> <p>18. श्री नितिन गोयल</p> <p>19. श्री पंकज कुमार</p> <p>20. श्री आशीष विश्वकर्मा</p> <p>21. श्री गौरव जैन</p> <p>22. श्री बालू लाल धाकड़</p> <p>23. श्री रीतेश लाल</p> <p>24. श्री प्रेम कुमार</p> <p>25. श्री महेन्दर जे. दुबे</p>
8.	पहल —	<p>26. श्री मोहम्मद शाहिद</p> <p>27. श्री अंजनी कुमार मलिक</p> <p>28. श्री दर्शन</p> <p>राजर्षि शाहू सर्वांगीण कार्यक्रम, जिला परिषद्, कोल्हापुर महाराष्ट्र</p>
9.	<p>दल के सदस्यों के नाम :</p> <p>पहल —</p> <p>दल के सदस्यों के नाम :</p>	<p>(i) श्री देशमुख प्रभाकर कृष्णा जी, भा.प्र.से.</p> <p>(ii) श्री माने महावीर दामोदर</p> <p>दिल्ली सरकार विद्यालय पद्धति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में मूलभूत सुधार</p> <p>(i) श्री राजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.</p> <p>(ii) श्री विजय कुमार, भा.प्र.से.</p>

8.	Initiative -	11. Shri G.J.Jerrie Auric Singh 12. Shri Kapil Bhagat 13. Shri Projinesh Biswas 14. Shri Dileep Mishra 15. Shri Sandeep Kumar Vats 16. Shri Ashish Arora 17. Shri Gaurav D. Johari 18. Shri Nitin Goyal 19. Shri Pankaj Kumar 20. Shri Ashish Vishwakarma 21. Shri Gaurav Jain 22. Shri Balu Lal Dhaker 23. Shri Ritesh Lal 24. Shri Prem Kumar 25. Shri Mahender J.Dubey 26. Shri Mohd. Shahid 27. Shri Anjani Kumar Malik 28. Shri Darshan Rajarshi Shahu Sarvangin Karyakram, Zilla Parishad, Kolhapur, Maharashtra
9.	Names of the Team Members : Initiative -	(i) Shri Deshmukh Prabhakar Krishnaji, IAS (ii) Shri Mane Mahavir Damodar Radical Improvement in Delhi Government School System, Government of NCT of Delhi
10.	Names of the Team Members Initiative -	(i) Sh. Rajendra Kumar, IAS (ii) Sh. Vijay Kumar, IAS (iii) Smt. Gitanjali G Kundra, IAS (iv) Sh. Ashok Kumar Extraordinary Performance in Emergent Situation of

10.	पहल – दल के सदस्यों के नाम :	(iii) श्रीमती गीतांजली जी कुन्द्रा, भा.प्र.से. (iv) श्री अशोक कुमार जम्मू और कश्मीर राज्य में भूकम्प की आपातिक स्थिति में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन (i) मि. बी.बी. व्यास, भा.प्र.से. (ii) मि. बशरत अहमद धर, भा.प्र.से. (iii) मि. बशीर अहमद रुनियाल, भा.प्र.से. (iv) मि. अब्दुल मजीद खाण्डेय, क.प्र. से.
11.	पहल –	(v) मि. जयपाल सिंह, क.प्र.से. (vi) मि. सईद शरीफ-उद-दीन, क.प्र.से. (vii) मि. मोहम्मद रमजान ठाकुर, क.प्र.से. जल एवं स्वच्छता प्रबंध संगठन
		(डब्ल्यू ए एस एम ओ)– “गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम भागीदारी पेयजल प्रदायगी पहुंच” – गुजरात सरकार
12.	पहल –	राज्य गरीबी उन्मूलन अभियान, कुडुम्बश्री – “आश्रय – निराश्रय पहचान, पुनर्वास और मॉनीटरिंग परियोजना” – केरल सरकार
13.	पहल –	इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवायें (ई-सेवा) आंध्र प्रदेश सरकार
14.	पहल –	उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओपीईपीए) –

“उड़ीसा में बाल खोज प्रणाली”

उड़ीसा सरकार

	Names of the Team Members :	Earthquake in the State of J&K. (i) Shri B.B.Vyas, IAS (ii) Shri Basharat Ahmad Dhar, IAS (iii) Shri Bashir Ahmad Runiyal, IAS (iv) Shri Abdul Majid Khanday, KAS (v) Shri Jai Pal Singh, KAS (vi) Shri Syed Sharief-ud-din, KAS (vii) Shri Mohammad Ramzan Thakur, KAS
11.	Initiative -	Water & Sanitation Management Organisation (WASMO) – ‘Innovative Participatory Drinking Water Delivery Approach in Rural Areas of Gujarat’ - Government of Gujarat
12.	Initiative -	State Poverty Eradication Mission, Kudumbashree - ‘Asraya - Destitute Identification, Rehabilitation and Monitoring Project’ - Government of Kerala
13.	Initiative -	Electronically Deliverable Services (e-Seva) - Government of Andhra Pradesh
14.	Initiative -	Orissa Primary Education Programme Authority (OPEPA) - ‘Child Tracking System in Orissa’ - Government of Orissa

दिनांक 21 अप्रैल, 2007 को प्रदान किये गये
वर्ष 2005-06 हेतु लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
प्रधानमंत्री पुरस्कार

1. श्री राजीव चावला, भा.प्र.से. – “भूमि-कर्नाटक में भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन प्रदायगी” पहल हेतु।
2. श्री आर एस पाण्डेय, भा.प्र.से. – “नागालैंड में सार्वजनिक संस्थानों और सेवाओं के सामुदायिकीकरण का कार्यक्रम” पहल हेतु।

**Prime Minister's Awards for Excellence in
Public Administration for the year 2005-06
presented on 21st April, 2007**

1. Shri Rajeev Chawla, IAS - for the initiative "Bhoomi - Online delivery of land records in Karnataka".
2. Shri R.S. Pandey, IAS - for the initiative "Programme of Communitization of Public Institutions and Services in Nagaland".